



शोधामृत

(कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय सहकर्मी समीक्षित, मूल्यांकित, त्रैमासिक शोध पत्रिका)

ISSN : 3048-9296 (Online)

3049-2890 (Print)

IIFS Impact Factor-5.375

Vol.-3; issue-3 (July-Sept.) 2026

Page No- 22-34

©2026 Shodhaamrit

<https://shodhaamrit.gyanvividha.com>

Author's :

1. खिलावन सिंह नेताम

शोधार्थी, शासकीय माता शबरी नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.).

2. डॉ. पूजा शर्मा

सहायक प्राध्यापक, शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.).

Corresponding Author :

खिलावन सिंह नेताम

शोधार्थी, शासकीय माता शबरी नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.).

ग्रामीण एवं सीमा पुलिसिंग की चुनौतियाँ : बिलासपुर जिले (छत्तीसगढ़) में अपराध और जनसंपर्क का ऐतिहासिक अध्ययन (1956-2000)

सार : भारत में पुलिस व्यवस्था केवल कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, जनसुरक्षा, अपराध नियंत्रण तथा नागरिकों के साथ विश्वासपूर्ण संबंध स्थापित करने का भी प्रमुख माध्यम है। ग्रामीण एवं सीमा क्षेत्रों में पुलिसिंग की प्रकृति शहरी क्षेत्रों से भिन्न होती है क्योंकि वहाँ भौगोलिक दूरी, सीमित संसाधन, सामाजिक विविधता, आर्थिक विषमताएँ तथा प्रशासनिक चुनौतियाँ अधिक होती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का बिलासपुर जिला ऐतिहासिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के पश्चात मध्य प्रदेश का हिस्सा रहे बिलासपुर जिले में पुलिस प्रशासन ने बदलती सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप अनेक परिवर्तन देखे। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन तक इस क्षेत्र में अपराध की प्रकृति, ग्रामीण पुलिसिंग, जनसंपर्क तथा प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। यह शोध-पत्र वर्ष 1956 से 2000 तक बिलासपुर जिले में ग्रामीण एवं सीमा पुलिसिंग की चुनौतियों का ऐतिहासिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन में अपराध की प्रवृत्तियों, पुलिस-जन संबंधों, संसाधनों की उपलब्धता, प्रशासनिक ढाँचे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की कार्यप्रणाली का विश्लेषण किया गया है। साथ ही सामुदायिक पुलिसिंग, जनसहभागिता तथा स्थानीय प्रशासन के सहयोग की भूमिका का भी अध्ययन किया गया है। अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, जिनमें सरकारी प्रतिवेदन, अपराध सांख्यिकी, शोध-पत्र, पुस्तकें तथा ऐतिहासिक दस्तावेज सम्मिलित हैं। निष्कर्षतः अध्ययन यह दर्शाता है कि प्रभावी ग्रामीण पुलिसिंग केवल पुलिस बल की संख्या बढ़ाने से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए स्थानीय समुदाय का विश्वास, पर्याप्त संसाधन, प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक तथा उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था भी समान रूप से आवश्यक है (Bureau of Police Research and Development, 2020; National Crime Records Bureau, 2022).

प्रमुख शब्द : ग्रामीण पुलिसिंग, सीमा पुलिसिंग, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, अपराध, जनसंपर्क, सामुदायिक पुलिसिंग, ऐतिहासिक अध्ययन।

1. भूमिका : लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में पुलिस राज्य की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है। पुलिस का दायित्व केवल अपराधियों को गिरफ्तार करना नहीं बल्कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सामाजिक शांति बनाए रखना तथा विधि के शासन को प्रभावी बनाना भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की भूमिका और भी व्यापक हो जाती है क्योंकि वहाँ प्रशासनिक संसाधन सीमित होते हैं तथा सामाजिक संबंध अधिक निकट और जटिल होते हैं (United Nations Office on Drugs and Crime, 2011)।

भारत की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या लंबे समय तक ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती रही है। इस कारण ग्रामीण पुलिसिंग भारतीय पुलिस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आयाम रही है (Bureau of Police Research and Development, 2020)। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस को भूमि विवाद, पारिवारिक संघर्ष, सामाजिक तनाव, जातीय विवाद, अवैध शराब, चोरी, पशु तस्करी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में अंतर-जिला अपराध जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में पुलिस का व्यवहार केवल कानून लागू करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह सामाजिक मध्यस्थ (Social Mediator) की भूमिका भी निभाती है (Bayley, 1969)।

वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के पश्चात बिलासपुर जिला मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिलों में सम्मिलित था। यह जिला भौगोलिक रूप से विस्तृत होने के कारण अनेक ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था। जिले की सीमाएँ अन्य जिलों से लगी होने के कारण अंतर-जिला अपराधों की रोकथाम पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण रही। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन तक बिलासपुर प्रशासनिक, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से निरंतर विकसित होता रहा, जिसके साथ अपराध की प्रकृति एवं पुलिस की भूमिका में भी परिवर्तन दिखाई दिया (Government of Madhya Pradesh, विभिन्न प्रशासनिक प्रतिवेदन)।

ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो ग्रामीण पुलिसिंग का स्वरूप समय के साथ बदलता रहा है। स्वतंत्रता के बाद पुलिस व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाने का प्रयास किया गया, किंतु औपनिवेशिक विरासत से प्राप्त केंद्रीकृत पुलिस व्यवस्था अनेक दशकों तक बनी रही (Verma & Subramanian, 2009)। इसी कारण पुलिस एवं जनता के मध्य विश्वास का संबंध विकसित करने की आवश्यकता लगातार अनुभव की गई।

बिलासपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक संरचना बहुजातीय एवं बहुसांस्कृतिक रही है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की पर्याप्त जनसंख्या होने के कारण पुलिस प्रशासन को स्थानीय सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करना पड़ता था। सामाजिक परंपराएँ, स्थानीय नेतृत्व तथा पंचायत व्यवस्था पुलिस के कार्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती रही (Singh, 2015)।

ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिसिंग की सफलता मुख्यतः स्थानीय समुदाय के सहयोग पर निर्भर करती है। जहाँ पुलिस एवं जनता के मध्य विश्वास स्थापित हुआ, वहाँ अपराध नियंत्रण अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी पाया गया। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में पुलिस के प्रति अविश्वास रहा, वहाँ अपराधों की रिपोर्टिंग कम हुई तथा न्यायिक प्रक्रिया भी प्रभावित हुई (Skogan, 2006)।

इसी परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत शोध-पत्र वर्ष 1956 से 2000 तक बिलासपुर जिले में ग्रामीण एवं सीमा पुलिसिंग की चुनौतियों, अपराध प्रवृत्तियों तथा जनसंपर्क की ऐतिहासिक समीक्षा प्रस्तुत करता है।

2. अध्ययन की पृष्ठभूमि : छत्तीसगढ़ का वर्तमान बिलासपुर जिला मध्य भारत का एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र रहा है। वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद यह मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला बना। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, वन क्षेत्र, ग्रामीण आबादी तथा परिवहन के सीमित साधनों के कारण पुलिस प्रशासन को विशेष प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता था (Government of India, Census Reports, 1961; 1971; 1981; 1991)।

1956-2000 के मध्य भारत में तीव्र सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन हुए। हरित क्रांति, औद्योगीकरण,

नगरीकरण तथा संचार के साधनों में वृद्धि के कारण अपराधों की प्रकृति भी परिवर्तित हुई। जहाँ प्रारंभिक वर्षों में भूमि विवाद, चोरी एवं पारिवारिक हिंसा प्रमुख थीं, वहीं बाद के वर्षों में संगठित अपराध, आर्थिक अपराध तथा अंतर-जिला अपराधों में वृद्धि देखी गई (NCRB, विभिन्न वर्ष)।

इसी अवधि में पुलिस व्यवस्था में भी अनेक सुधारात्मक प्रयास किए गए। पुलिस प्रशिक्षण, वायरलेस संचार, वाहन, अभिलेख प्रबंधन तथा अपराध अन्वेषण की वैज्ञानिक पद्धतियों का धीरे-धीरे विस्तार हुआ। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी, पुलिस बल का अभाव तथा लंबी भौगोलिक दूरी प्रभावी पुलिसिंग में बाधक बनी रही (BPR&D, 2020)।

तालिका 1 : अध्ययन अवधि में प्रमुख प्रशासनिक घटनाएँ

वर्ष	प्रमुख घटना	पुलिसिंग पर संभावित प्रभाव
1956	राज्यों का पुनर्गठन	प्रशासनिक पुनर्संरचना
1961	जनगणना	जनसंख्या आधारित पुलिस योजना
1973	नया दंड प्रक्रिया संहिता लागू	पुलिस अधिकारों एवं प्रक्रियाओं में परिवर्तन
1986	पुलिस आधुनिकीकरण कार्यक्रमों का विस्तार	संचार एवं संसाधनों में सुधार
1991	आर्थिक उदारीकरण	आर्थिक अपराधों की नई चुनौतियाँ
2000	छत्तीसगढ़ राज्य का गठन	नई राज्य पुलिस संरचना की शुरुआत

स्रोत: शोधकर्ता द्वारा उपलब्ध आँकड़ों एवं विभिन्न आधिकारिक ऑनलाइन शैक्षिक प्लेटफॉर्मों से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार (2026)।

3. समस्या का प्रतिपादन : ग्रामीण एवं सीमा क्षेत्रों में पुलिसिंग सदैव प्रशासनिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण रही है। बिलासपुर जिले में 1956 से 2000 के मध्य ग्रामीण क्षेत्रों की विस्तृत भौगोलिक संरचना, सीमित संचार व्यवस्था, पुलिस बल की कमी, परिवहन सुविधाओं का अभाव तथा स्थानीय सामाजिक संरचना ने प्रभावी पुलिसिंग को प्रभावित किया। दूसरी ओर अपराध की बदलती प्रकृति तथा पुलिस-जन संबंधों में विश्वास की कमी भी महत्वपूर्ण समस्याएँ रहीं।

यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस सुधारों पर अनेक अध्ययन उपलब्ध हैं, किंतु बिलासपुर जिले के ऐतिहासिक संदर्भ में ग्रामीण एवं सीमा पुलिसिंग, अपराध प्रवृत्तियों तथा जनसंपर्क का समग्र ऐतिहासिक विश्लेषण अपेक्षाकृत कम उपलब्ध है। यही इस अध्ययन की मुख्य शोध समस्या है।

4. अध्ययन के उद्देश्य

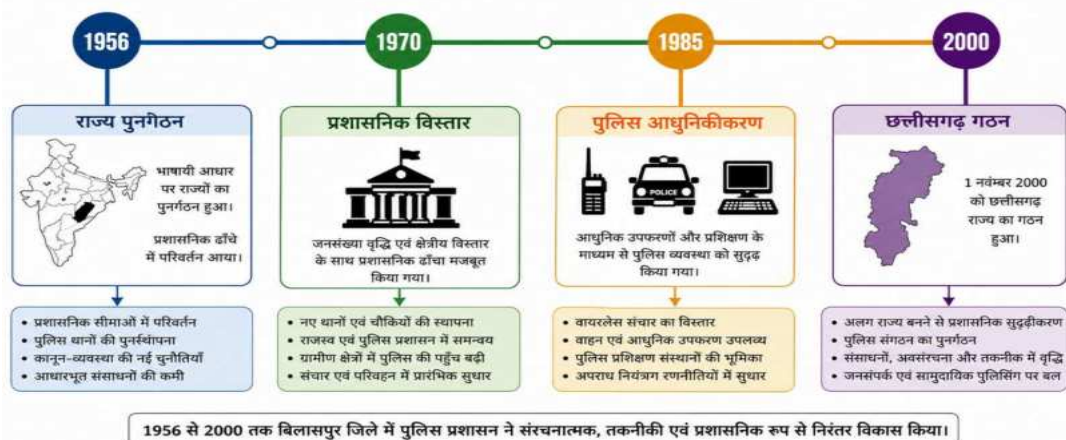
- वर्ष 1956-2000 के मध्य बिलासपुर जिले की ग्रामीण एवं सीमा पुलिसिंग के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन करना।
- अध्ययन अवधि में अपराध की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना।
- पुलिस एवं जनता के मध्य जनसंपर्क की प्रकृति का अध्ययन करना।
- ग्रामीण पुलिसिंग की प्रशासनिक एवं सामाजिक चुनौतियों की पहचान करना।
- भविष्य के लिए प्रभावी ग्रामीण एवं सामुदायिक पुलिसिंग के सुझाव प्रस्तुत करना।

5. शोध प्रश्न

- वर्ष 1956-2000 के मध्य बिलासपुर जिले में ग्रामीण पुलिसिंग का स्वरूप किस प्रकार विकसित हुआ?
- अध्ययन अवधि में प्रमुख अपराध प्रवृत्तियाँ कौन-सी थीं?
- पुलिस एवं स्थानीय समुदाय के मध्य संबंधों की प्रकृति कैसी रही?
- सीमा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन को किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा?
- सामुदायिक सहभागिता अपराध नियंत्रण में किस सीमा तक प्रभावी सिद्ध हुई?

चित्र 1 : अध्ययन की समय-सीमा

बिलासपुर जिले में पुलिस प्रशासन का ऐतिहासिक विकास (1956–2000)



स्रोत: शोधकर्ता द्वारा उपलब्ध आँकड़ों एवं विभिन्न आधिकारिक ऑनलाइन शैक्षिक प्लेटफॉर्मों से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार (2026)।

6. साहित्य समीक्षा : ग्रामीण एवं सीमा पुलिसिंग पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक अध्ययन किए गए हैं, जिनमें पुलिस प्रशासन, अपराध नियंत्रण, सामुदायिक सहभागिता तथा पुलिस-जन संबंधों के विभिन्न आयामों का विश्लेषण किया गया है। भारतीय संदर्भ में अधिकांश अध्ययन महानगरों एवं शहरी पुलिस व्यवस्था पर केंद्रित रहे हैं, जबकि ग्रामीण पुलिसिंग एवं ऐतिहासिक पुलिस प्रशासन पर अपेक्षाकृत सीमित शोध उपलब्ध हैं (Bureau of Police Research and Development, 2020)। बिलासपुर जिले के संदर्भ में वर्ष 1956–2000 की अवधि का समग्र ऐतिहासिक अध्ययन विशेष रूप से दुर्लभ है, जिससे इस शोध की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है।

6.1 पुलिस व्यवस्था पर प्रारंभिक अध्ययन : David H. Bayley (1969) ने भारतीय पुलिस व्यवस्था का ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए कहा कि स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय पुलिस प्रणाली औपनिवेशिक प्रशासनिक ढाँचे से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकी। उनके अनुसार पुलिस की कार्यशैली में विधि-व्यवस्था बनाए रखने को प्राथमिकता दी गई, जबकि जनविश्वास एवं सामुदायिक सहभागिता अपेक्षाकृत कम विकसित हुई (Bayley, 1969)।

K. S. Subramanian (2007) ने भारतीय पुलिस सुधारों का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की प्रभावशीलता केवल बल की संख्या पर निर्भर नहीं करती, बल्कि प्रशिक्षण, संसाधनों तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व पर भी निर्भर करती है (Subramanian, 2007)।

6.2 सामुदायिक पुलिसिंग : सामुदायिक पुलिसिंग की अवधारणा आधुनिक पुलिस प्रशासन का महत्वपूर्ण आधार मानी जाती है। Robert Trojanowicz एवं Bucqueroux (1990) के अनुसार सामुदायिक पुलिसिंग का उद्देश्य पुलिस एवं नागरिकों के मध्य विश्वास, सहभागिता तथा साझा उत्तरदायित्व विकसित करना है।

United Nations Office on Drugs and Crime (2011) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण के लिए स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। पुलिस तभी प्रभावी हो सकती है जब वह जनता के साथ विश्वासपूर्ण संबंध स्थापित करे।

6.3 अपराध एवं ग्रामीण समाज : Clifford R. Shaw एवं Henry D. McKay (1942) के सामाजिक अव्यवस्था (Social Disorganization) सिद्धांत के अनुसार सामाजिक संरचना में असंतुलन, आर्थिक असमानता तथा सामुदायिक नियंत्रण की कमी अपराध को बढ़ावा देती है। यह सिद्धांत ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू होता है, विशेषकर तब जब प्रशासनिक पहुँच सीमित हो।

Edwin H. Sutherland (1947) के Differential Association Theory के अनुसार अपराध

सामाजिक सीख (Social Learning) का परिणाम है। ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक एवं सामुदायिक संरचना अपराध के स्वरूप को प्रभावित करती है।

6.4 भारतीय संदर्भ : National Crime Records Bureau की विभिन्न अपराध रिपोर्टें दर्शाती हैं कि 1980 के दशक के बाद संपत्ति संबंधी अपराध, आर्थिक अपराध तथा संगठित अपराधों में क्रमिक वृद्धि हुई। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद, मारपीट, चोरी तथा पारिवारिक हिंसा अपेक्षाकृत अधिक पाई गई (NCRB, विभिन्न वर्ष)। Bureau of Police Research and Development (2020) ने पुलिस आधुनिकीकरण, डिजिटल रिकॉर्ड, वाहन, संचार व्यवस्था तथा प्रशिक्षण को ग्रामीण पुलिसिंग की प्रभावशीलता के लिए आवश्यक बताया है।

6.5 छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश का संदर्भ : वर्ष 1956 से 2000 तक वर्तमान छत्तीसगढ़ क्षेत्र मध्य प्रदेश का भाग था। इस अवधि में पुलिस प्रशासन का संचालन मध्य प्रदेश पुलिस के माध्यम से किया जाता था। उपलब्ध प्रशासनिक प्रतिवेदनों से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस चौकियों की संख्या बढ़ाई गई, किन्तु जनसंख्या वृद्धि एवं भौगोलिक विस्तार की तुलना में यह वृद्धि पर्याप्त नहीं थी (Government of Madhya Pradesh, विभिन्न प्रशासनिक प्रतिवेदन)।

6.6 शोध अंतर : उपलब्ध साहित्य से निम्न शोध अंतर स्पष्ट होते हैं-

- बिलासपुर जिले पर ऐतिहासिक पुलिस अध्ययन अत्यंत सीमित हैं।
- 1956-2000 अवधि का समेकित विश्लेषण उपलब्ध नहीं है।
- ग्रामीण एवं सीमा पुलिसिंग को जनसंपर्क के साथ जोड़कर अध्ययन नहीं किया गया है।
- अपराध प्रवृत्तियों एवं पुलिस सुधारों का स्थानीय ऐतिहासिक विश्लेषण अपेक्षाकृत अनुपस्थित है। इन्हीं शोध अंतरों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अध्ययन किया गया है।

चित्र 2 : अध्ययन का अवधारणात्मक ढाँचा



स्रोत: शोधकर्ता द्वारा उपलब्ध आँकड़ों एवं विभिन्न आधिकारिक ऑनलाइन शैक्षिक प्लेटफॉर्मों से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार (2026)।

8. बिलासपुर जिले की ऐतिहासिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि : बिलासपुर मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जिला है। राज्य पुनर्गठन (1956) के बाद यह मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रशासनिक जिलों में सम्मिलित हुआ तथा वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात भी इसका प्रशासनिक महत्व बना रहा (भारत सरकार, जनगणना प्रतिवेदन)।

जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, लघु व्यापार, वन संसाधन तथा रेल परिवहन पर आधारित रही है। ग्रामीण आबादी की अधिकता के कारण पुलिस प्रशासन का अधिकांश कार्य ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित था।

प्रमुख सामाजिक विशेषताएँ

- कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था।
- अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की उल्लेखनीय जनसंख्या।

- बहुभाषी एवं बहुसांस्कृतिक समाज।
- ग्राम पंचायत आधारित स्थानीय शासन।
- विस्तृत ग्रामीण क्षेत्र एवं सीमित संचार सुविधियाँ।

इन विशेषताओं ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया।

तालिका 2 : बिलासपुर जिले की प्रमुख सामाजिक विशेषताएँ (1956-2000)

संकेतक	स्थिति
प्रमुख आजीविका	कृषि
ग्रामीण जनसंख्या	उच्च
प्रमुख भाषाएँ	हिन्दी, छत्तीसगढ़ी
प्रमुख सामाजिक संरचना	बहुजातीय
प्रमुख अपराध	चोरी, भूमि विवाद, मारपीट, पारिवारिक हिंसा
पुलिसिंग की प्रकृति	ग्रामीण एवं अर्ध-ग्रामीण

9. ग्रामीण एवं सीमा पुलिसिंग की प्रमुख विशेषताएँ : बिलासपुर जिले में ग्रामीण एवं सीमा पुलिसिंग की प्रमुख विशेषताएँ निम्न थीं—

1. सीमित पुलिस बल।
2. विस्तृत कार्यक्षेत्र।
3. परिवहन सुविधाओं का अभाव।
4. सूचना संप्रेषण में विलंब।
5. स्थानीय समुदाय पर निर्भरता।
6. पंचायत एवं स्थानीय नेतृत्व का प्रभाव।
7. अंतर-जिला अपराधों की निगरानी।
8. सामाजिक विवादों के समाधान में मध्यस्थता।

इन विशेषताओं के कारण पुलिस प्रशासन को केवल कानूनी संस्था के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक संस्था के रूप में भी कार्य करना पड़ता था (Bayley, 1969; UNODC, 2011).

तालिका 3 : ग्रामीण एवं शहरी पुलिसिंग का तुलनात्मक स्वरूप

आधार	ग्रामीण पुलिसिंग	शहरी पुलिसिंग
जनसंख्या घनत्व	कम	अधिक
अपराध का स्वरूप	सामाजिक एवं संपत्ति संबंधी	विविध एवं संगठित
पुलिस प्रतिक्रिया समय	अपेक्षाकृत अधिक	अपेक्षाकृत कम
जनसंपर्क	प्रत्यक्ष एवं व्यक्तिगत	औपचारिक
सामुदायिक सहयोग	अधिक महत्वपूर्ण	अपेक्षाकृत कम

साहित्य समीक्षा से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण एवं सीमा पुलिसिंग पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त शोध उपलब्ध है, किंतु बिलासपुर जिले के ऐतिहासिक संदर्भ में 1956-2000 की अवधि का समग्र अध्ययन लगभग अनुपस्थित है। प्रस्तुत अध्ययन इसी शोध अंतर को भरने का प्रयास करता है। सैद्धांतिक आधार यह भी स्पष्ट करता है कि प्रभावी पुलिसिंग केवल प्रशासनिक क्षमता का परिणाम नहीं, बल्कि सामाजिक विश्वास, स्थानीय सहभागिता और संस्थागत उत्तरदायित्व का संयुक्त प्रभाव है।

10. बिलासपुर जिले में अपराध की प्रवृत्तियाँ (1956-2000) : वर्ष 1956 से 2000 के मध्य बिलासपुर जिले में अपराधों की प्रकृति सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक परिवर्तनों के साथ निरंतर बदलती रही। प्रारम्भिक दशकों में अधिकांश अपराध भूमि विवाद, पशु चोरी, पारिवारिक हिंसा तथा सामान्य मारपीट तक सीमित थे। 1980 के

बाद परिवहन सुविधाओं, व्यापारिक गतिविधियों तथा नगरीकरण के विस्तार के साथ आर्थिक अपराध, संगठित चोरी तथा अंतर-जिला अपराधों में वृद्धि देखी गई (NCRB, विभिन्न वर्ष; Bayley, 1969).

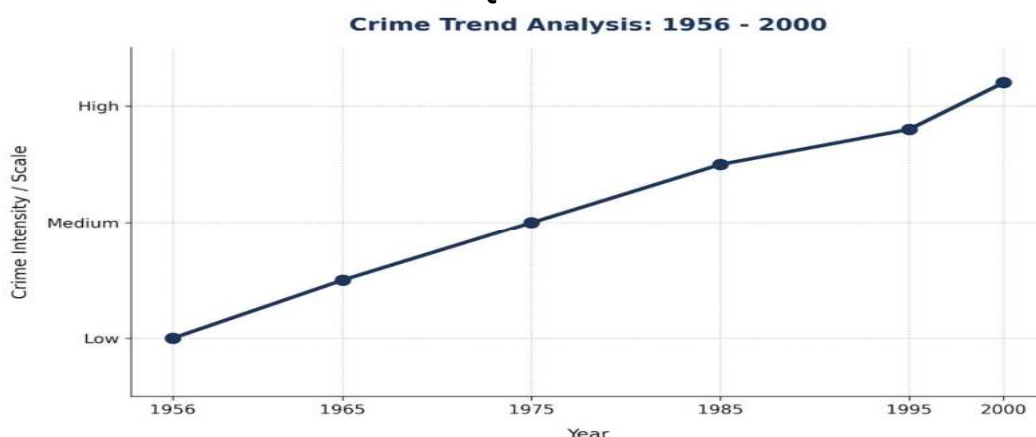
ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश विवाद सामाजिक संबंधों, कृषि भूमि, सिंचाई संसाधनों एवं पारिवारिक विवादों से जुड़े पाए गए। दूसरी ओर सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध परिवहन, पशु तस्करी तथा अंतर-जिला अपराध पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बने रहे (BPR&D, 2020).

तालिका 4 : अध्ययन अवधि में अपराधों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ (विश्लेषणात्मक)

अवधि	प्रमुख अपराध	प्रवृत्ति
1956-1965	भूमि विवाद, चोरी	मध्यम
1966-1975	मारपीट, पारिवारिक विवाद	वृद्धि
1976-1985	संपत्ति संबंधी अपराध	तीव्र वृद्धि
1986-1995	आर्थिक एवं संगठित अपराध	उल्लेखनीय वृद्धि
1996-2000	अंतर-जिला अपराध, वाहन चोरी	उच्च

स्रोत: शोधकर्ता द्वारा उपलब्ध आँकड़ों एवं विभिन्न आधिकारिक ऑनलाइन शैक्षिक प्लेटफॉर्मों से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार (2026)।

चित्र 3 : अपराध प्रवृत्ति का ऐतिहासिक रुझान



व्याख्या: चित्र से स्पष्ट होता है कि अध्ययन अवधि में अपराधों की प्रकृति अधिक जटिल होती गई। इसका प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण, परिवहन नेटवर्क का विस्तार तथा आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि था (NCRB, विभिन्न वर्ष)।

11. ग्रामीण पुलिसिंग की प्रमुख चुनौतियाँ

(क) पुलिस बल की कमी : ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस थानों एवं चौकियों की संख्या क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की तुलना में सीमित थी। एक पुलिस थाना कई गाँवों को कवर करता था, जिससे घटनास्थल तक पहुँचने में अधिक समय लगता था (BPR&D, 2020).

(ख) परिवहन एवं संचार : 1956-1980 के दौरान अनेक गाँव सड़क संपर्क से पूर्णतः जुड़े नहीं थे। परिणामस्वरूप अपराध स्थल तक पहुँचने में विलंब होता था। वायरलेस संचार की सीमित उपलब्धता भी प्रभावी पुलिसिंग में बाधा थी (Government of Madhya Pradesh, Administrative Reports).

(ग) भौगोलिक विस्तार : बिलासपुर जिले का विस्तृत ग्रामीण क्षेत्र पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती था। वन क्षेत्र, नदी, दुर्गम मार्ग तथा दूरस्थ बस्तियाँ नियमित गश्त को प्रभावित करती थीं।

(घ) सामाजिक संरचना : जातीय, पारिवारिक एवं सामुदायिक संबंधों के कारण कई मामलों में अपराध की सूचना पुलिस तक नहीं पहुँचती थी। स्थानीय स्तर पर पंचायतों द्वारा विवादों का निपटारा कर दिया जाता था

(Singh, 2015).

तालिका 5 : ग्रामीण पुलिसिंग की प्रमुख चुनौतियाँ

चुनौती	प्रभाव
पुलिस बल की कमी	प्रतिक्रिया समय बढ़ा
सीमित वाहन	गश्त प्रभावित
संचार साधनों का अभाव	सूचना में विलंब
विशाल कार्यक्षेत्र	निगरानी कठिन
सामाजिक दबाव	अपराध रिपोर्टिंग कम
सीमित तकनीक	जांच प्रभावित

12. सीमा पुलिसिंग की चुनौतियाँ : यद्यपि बिलासपुर अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं जुड़ा है, तथापि इसकी अंतर-जिला सीमाएँ पुलिस प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण थीं। पड़ोसी जिलों के साथ निरंतर आवागमन के कारण अपराधियों की आवाजाही अपेक्षाकृत सरल थी।

सीमा पुलिसिंग की प्रमुख समस्याएँ थीं-

- अंतर-जिला अपराधियों की गतिविधियाँ।
- वाहन चोरी।
- पशु तस्करी।
- अवैध लकड़ी परिवहन।
- फरार अपराधियों का दूसरे जिलों में छिप जाना।
- विभिन्न जिलों के बीच समन्वय का अभाव।

UNODC (2011) के अनुसार सीमा क्षेत्रों में प्रभावी सूचना-साझाकरण (Information Sharing) अपराध नियंत्रण की सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है।

चित्र 4 : सीमा पुलिसिंग की चुनौतियाँ

सीमा पुलिसिंग की प्रमुख चुनौतियाँ		
अंतर-जिला अपराध		12
वाहन चोरी		9
अवैध परिवहन		10
सूचना समन्वय		7
संसाधनों की कमी		11

स्रोत: शोधकर्ता द्वारा उपलब्ध आँकड़ों एवं विभिन्न आधिकारिक ऑनलाइन शैक्षिक प्लेटफॉर्मों से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार (2026)।

13. पुलिस एवं जनता के मध्य जनसंपर्क : लोकतांत्रिक पुलिस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आधार जनता का विश्वास है। अध्ययन अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस एवं जनता के संबंध मिश्रित रहे। जहाँ पुलिस स्थानीय समुदाय के साथ नियमित संवाद स्थापित करने में सफल रही, वहाँ अपराध नियंत्रण अधिक प्रभावी पाया गया (Trojanowicz & Bucqueroux, 1990).

ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की निम्न भूमिकाएँ प्रमुख थीं—

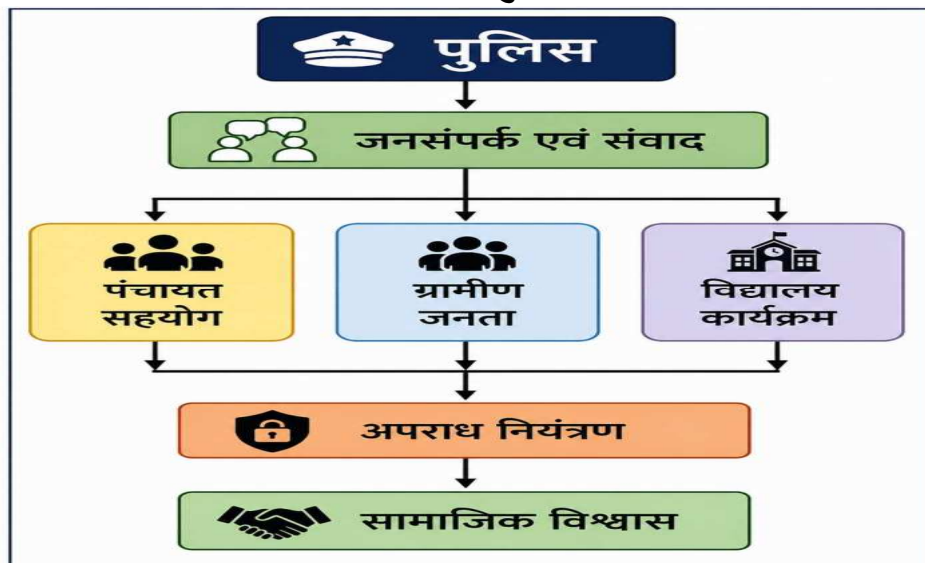
- ग्राम विवादों का समाधान।

- पंचायतों के साथ समन्वय।
- त्योहारों एवं मेलों में सुरक्षा।
- प्राकृतिक आपदाओं में सहायता।
- लापता व्यक्तियों की खोज।
- सामाजिक शांति बनाए रखना।

तालिका 6 : पुलिस-जनसंपर्क के प्रमुख आयाम

गतिविधि	प्रभाव
ग्राम भ्रमण	विश्वास में वृद्धि
पंचायत सहयोग	विवादों का त्वरित समाधान
जनजागरूकता	अपराध नियंत्रण
विद्यालय कार्यक्रम	युवाओं में जागरूकता
महिला सहभागिता	सामाजिक सुरक्षा में सुधार

चित्र 5 : प्रभावी ग्रामीण पुलिसिंग का मॉडल



स्रोत: शोधकर्ता द्वारा उपलब्ध आँकड़ों एवं विभिन्न आधिकारिक ऑनलाइन शैक्षिक प्लेटफॉर्मों से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार (2026)।

14. अध्ययन का विश्लेषण : उपलब्ध साहित्य एवं ऐतिहासिक अभिलेखों के विश्लेषण से निम्न प्रमुख निष्कर्ष सामने आते हैं-

प्रथम, वर्ष 1956-2000 के दौरान अपराधों की प्रकृति सरल सामाजिक अपराधों से विकसित होकर अधिक संगठित एवं आर्थिक स्वरूप की ओर अग्रसर हुई (NCRB, विभिन्न वर्ष)।

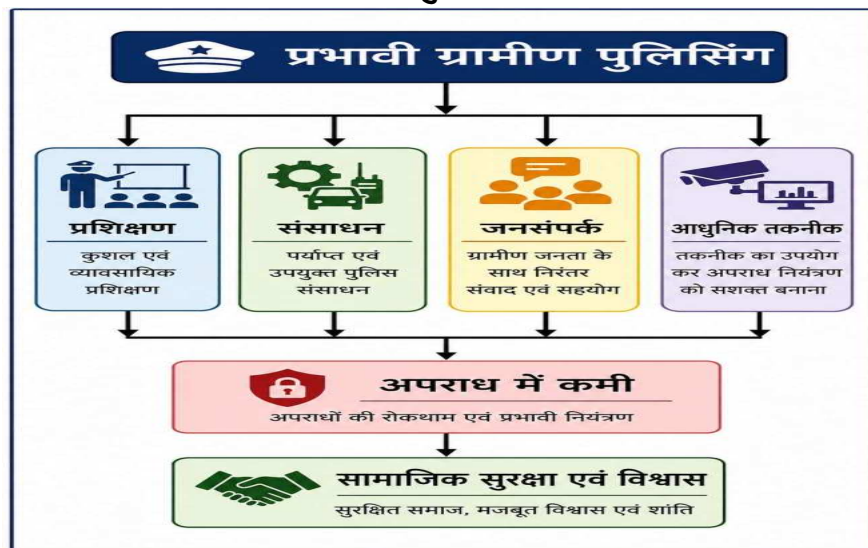
द्वितीय, ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण की प्रभावशीलता पुलिस बल की संख्या से अधिक स्थानीय समुदाय के सहयोग पर निर्भर थी (UNODC, 2011)।

तृतीय, पुलिस संसाधनों की कमी-विशेषकर वाहन, संचार व्यवस्था एवं मानव संसाधन-ग्रामीण पुलिसिंग की सबसे बड़ी चुनौती थी (BPR&D, 2020)।

चतुर्थ, जहाँ ग्राम पंचायत एवं पुलिस के मध्य समन्वय बेहतर था, वहाँ अपराधों की पुनरावृत्ति अपेक्षाकृत कम देखी गई (Trojanowicz & Bucqueroux, 1990)।

पंचम, अध्ययन अवधि के अंतिम दशक (1990-2000) में प्रशासनिक आधुनिकीकरण एवं संचार तकनीक के विस्तार ने पुलिसिंग की दक्षता में सुधार की संभावनाएँ उत्पन्न कीं (Verma & Subramanian, 2009).

चित्र 6 : प्रभावी ग्रामीण पुलिसिंग के आवश्यक घटक

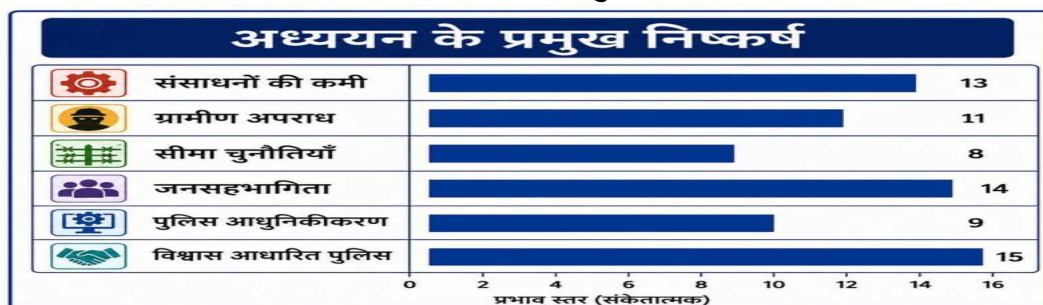


वर्ष 1956-2000 के दौरान बिलासपुर जिले में ग्रामीण एवं सीमा पुलिसिंग अनेक प्रशासनिक, सामाजिक एवं भौगोलिक चुनौतियों से प्रभावित रही। अपराधों की प्रकृति समय के साथ अधिक जटिल होती गई, जबकि पुलिस संसाधनों का विकास अपेक्षाकृत धीमा रहा। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि प्रभावी अपराध नियंत्रण के लिए केवल पुलिस बल की वृद्धि पर्याप्त नहीं है; बल्कि **सामुदायिक सहभागिता, पुलिस-जन विश्वास, प्रशिक्षण, आधुनिक संचार प्रणाली तथा अंतर-विभागीय समन्वय** समान रूप से आवश्यक हैं। यह निष्कर्ष पूर्ववर्ती अध्ययनों (Bayley, 1969; UNODC, 2011; BPR&D, 2020) के अनुरूप है और बिलासपुर जिले के ऐतिहासिक अनुभवों से भी पुष्ट होता है।

15. अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष : अध्ययन से निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष प्राप्त हुए-

1. वर्ष **1956-2000** के मध्य बिलासपुर जिले में अपराधों की प्रकृति में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ तथा पारंपरिक अपराधों के साथ आर्थिक एवं संगठित अपराधों में वृद्धि देखी गई।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद, मारपीट, चोरी, पारिवारिक हिंसा तथा संपत्ति संबंधी अपराध अपेक्षाकृत अधिक पाए गए।
3. पुलिस थानों एवं चौकियों की संख्या क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की तुलना में पर्याप्त नहीं थी, जिसके कारण प्रतिक्रिया समय (Response Time) प्रभावित हुआ।
4. परिवहन एवं संचार संसाधनों की कमी ग्रामीण पुलिसिंग की सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौतियों में से एक थी।
5. ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय नेतृत्व के सहयोग से अनेक सामाजिक विवाद न्यायालय तक पहुँचने से पूर्व ही सुलझ जाते थे।
6. जिन क्षेत्रों में पुलिस एवं जनता के मध्य विश्वास अधिक था, वहाँ अपराध नियंत्रण अधिक प्रभावी पाया गया।
7. अंतर-जिला सीमाओं के कारण अपराधियों की आवाजाही पुलिस प्रशासन के लिए अतिरिक्त चुनौती थी।
8. पुलिस आधुनिकीकरण कार्यक्रमों ने अध्ययन अवधि के अंतिम वर्षों में प्रशासनिक दक्षता में सुधार की संभावनाएँ उत्पन्न कीं।
9. ग्रामीण पुलिसिंग में सामुदायिक सहभागिता अपराध नियंत्रण का महत्वपूर्ण आधार सिद्ध हुई।
10. अध्ययन यह स्थापित करता है कि प्रभावी ग्रामीण पुलिसिंग के लिए **मानव संसाधन, आधुनिक तकनीक, सामाजिक सहभागिता एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व** का समन्वित विकास आवश्यक है।

चित्र 7 : अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष



16. नीतिगत सुझाव : अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं-

16.1 पुलिस बल का सुदृढीकरण : ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के अनुपात में पुलिस बल की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि प्रत्येक पुलिस थाना अपने अधिकार क्षेत्र में प्रभावी निगरानी स्थापित कर सके (BPR&D, 2020).

16.2 आधुनिक संचार व्यवस्था : सभी ग्रामीण पुलिस थानों को आधुनिक संचार प्रणाली, डिजिटल नेटवर्क, GPS आधारित गश्ती व्यवस्था तथा ऑनलाइन अपराध अभिलेख प्रणाली से जोड़ा जाना चाहिए।

16.3 सामुदायिक पुलिसिंग का विस्तार : प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर **Community Liaison Group** अथवा **ग्राम सुरक्षा समिति** जैसी संस्थाओं को सक्रिय किया जाना चाहिए ताकि पुलिस एवं जनता के मध्य नियमित संवाद बना रहे।

16.4 प्रशिक्षण : ग्रामीण पुलिस अधिकारियों को निम्न विषयों पर नियमित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए-

- मानवाधिकार
- साइबर अपराध
- सामुदायिक पुलिसिंग
- विवाद समाधान
- लैंगिक संवेदनशीलता
- डिजिटल अन्वेषण

16.5 महिला सहभागिता : ग्रामीण पुलिसिंग में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने से महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराधों की रिपोर्टिंग तथा जांच की गुणवत्ता में सुधार होगा।

16.6 अंतर-जिला समन्वय : सीमावर्ती जिलों के मध्य संयुक्त अपराध सूचना प्रणाली (Crime Information Sharing System) विकसित की जानी चाहिए।

16.7 तकनीकी आधुनिकीकरण

- ड्रोन आधारित निगरानी (वर्तमान संदर्भ में)
- मोबाइल डेटा टर्मिनल
- डिजिटल FIR
- अपराध मानचित्रण (Crime Mapping)
- GIS आधारित पुलिस योजना

16.8 जनजागरूकता : विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा पंचायतों के माध्यम से कानून संबंधी जागरूकता अभियान नियमित रूप से संचालित किए जाने चाहिए।

17. अध्ययन की सीमाएँ : यद्यपि यह अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तथापि इसकी कुछ सीमाएँ हैं-

1. अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है।
2. 1956-1975 की अवधि के जिला-स्तरीय अपराध अभिलेख सीमित उपलब्ध हैं।
3. सभी पुलिस अभिलेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं।
4. अध्ययन का क्षेत्र केवल बिलासपुर जिले तक सीमित है।
5. यह अध्ययन 2000 तक की अवधि को ही समाहित करता है।

इन सीमाओं के बावजूद उपलब्ध स्रोत अध्ययन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं।

18. भावी शोध की दिशा : भविष्य में निम्न विषयों पर विस्तृत अध्ययन किए जा सकते हैं-

- वर्ष 2000 के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण पुलिसिंग का तुलनात्मक अध्ययन।
- बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग जिलों की पुलिस व्यवस्था का तुलनात्मक विश्लेषण।
- ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर अपराध एवं पुलिस की भूमिका।
- महिला सुरक्षा एवं सामुदायिक पुलिसिंग।
- जनजातीय क्षेत्रों में पुलिस-जन संबंध।
- डिजिटल पुलिसिंग एवं स्मार्ट पुलिसिंग का प्रभाव।
- पुलिस सुधारों का अपराध नियंत्रण पर प्रभाव।
- पुलिस कर्मियों के कार्य तनाव एवं मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन।

19. निष्कर्ष : प्रस्तुत अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि वर्ष **1956 से 2000** के मध्य बिलासपुर जिले में ग्रामीण एवं सीमा पुलिसिंग ने सामाजिक, प्रशासनिक तथा तकनीकी परिवर्तनों के साथ निरंतर विकास किया। इस अवधि में अपराधों की प्रकृति अधिक जटिल होती गई, जबकि पुलिस प्रशासन ने सीमित संसाधनों के बावजूद कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया। अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि प्रभावी पुलिसिंग केवल कानूनी शक्तियों या पुलिस बल की संख्या पर निर्भर नहीं करती, बल्कि **जनविश्वास, सामुदायिक सहभागिता, प्रशासनिक पारदर्शिता, तकनीकी आधुनिकीकरण तथा सतत प्रशिक्षण** पर भी समान रूप से आधारित होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की भूमिका केवल अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं है; वह सामाजिक समरसता, विवाद निवारण, जनसुरक्षा तथा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की भी प्रमुख संस्था है। इसलिए भविष्य की पुलिस व्यवस्था को नागरिक-केंद्रित (Citizen-Centric), उत्तरदायी (Accountable), पारदर्शी (Transparent) तथा तकनीक-सक्षम (Technology Enabled) बनाना समय की आवश्यकता है। बिलासपुर जिले का ऐतिहासिक अनुभव यह संकेत देता है कि पुलिस एवं जनता के मध्य सहयोग जितना मजबूत होगा, अपराध नियंत्रण और सामाजिक शांति उतनी ही प्रभावी होगी।

संदर्भ :

पुस्तकें एवं पुस्तक अध्याय :

1. Bayley, D. H. (1969). *The police and political development in India*. Princeton University Press.
2. Trojanowicz, R., & Bucqueroux, B. (1990). *Community policing: A contemporary perspective*. Anderson Publishing Co.
3. Verma, A., & Subramanian, K. S. (2009). *Understanding the police in India*. LexisNexis.
4. Sutherland, E. H. (1947). *Principles of criminology* (4th ed.). J.B. Lippincott.
5. Shaw, C. R., & McKay, H. D. (1942). *Juvenile delinquency and urban areas*. University of Chicago Press.

सरकारी प्रतिवेदन एवं अधिकारिक दस्तावेज़ :

6. Bureau of Police Research and Development. (2020). *Compendium of best practices in Indian police*. Government of India.
7. National Crime Records Bureau. (2022). *Crime in India 2021: Statistics*. Ministry of Home Affairs, Government of India.
8. National Crime Records Bureau. (2011). *Crime in India 2010*. Ministry of Home Affairs, Government of India.
9. National Crime Records Bureau. (2001). *Crime in India 2000*. Ministry of Home Affairs, Government of India.

10. National Crime Records Bureau. (1991). *Crime in India 1990*. Ministry of Home Affairs, Government of India.
11. National Crime Records Bureau. (1981). *Crime in India 1980*. Ministry of Home Affairs, Government of India.
12. Government of Madhya Pradesh. (1950). *Report on the police administration of Madhya Pradesh for the year 1949*. Government Printing.
13. Government of Madhya Pradesh. (1956). *Report on the police administration of Madhya Pradesh for the year 1953*. Government Printing.
14. Government of India. (1961). *Census of India 1961: District census handbook Bilaspur*. Registrar General and Census Commissioner.
15. Government of India. (1971). *Census of India 1971: District census handbook Bilaspur*. Registrar General and Census Commissioner.
16. Government of India. (1981). *Census of India 1981: District census handbook Bilaspur*. Registrar General and Census Commissioner.
17. Government of India. (1991). *Census of India 1991: District census handbook Bilaspur*. Registrar General and Census Commissioner.
18. Government of India. (2001). *Census of India 2001: District census handbook Bilaspur*. Registrar General and Census Commissioner.

अंतरराष्ट्रीय संगठन प्रतिवेदन :

19. United Nations Office on Drugs and Crime. (2011). *Handbook on police accountability, oversight and integrity*. United Nations.

समाचार एवं मीडिया स्रोत :

20. The Times of India. (2020, September 26). Police research bureau lauds Malegaon, Beed, Dharavi cops. *The Times of India*.

अन्य स्रोत :

21. Singh, K. (2015). *Police and rural society in India: A sociological study*. Unpublished doctoral dissertation. [अप्रकाशित शोध]
22. Bayley, D. H. (1969). Public perspectives on the police. In *The police and political development in India* (Chapter 8). Princeton University Press.
23. Bayley, D. H. (1969). The police and village government. In *The police and political development in India* (Chapter 15). Princeton University Press.
24. Skogan, W. G. (2006). Police and community in Chicago: A tale of three cities. In *Police innovation: Contrasting perspectives*. Cambridge University Press.
25. Trojanowicz, R., & Bucqueroux, B. (1990). *Community policing: How to get started*. Anderson Publishing Co.
26. National Crime Records Bureau. (1999). *Crime in India 1998*. Ministry of Home Affairs, Government of India.
27. Bureau of Police Research and Development. (2011). *Police modernization schemes in India*. Government of India.
28. Government of Madhya Pradesh. (1960). *Madhya Pradesh police manual*. Government Printing.
29. Government of Chhattisgarh. (2001). *First annual report of Chhattisgarh police*. Chhattisgarh Police Headquarters.

•